Punjab and U.P., which are in different stages of processing for sanction as per the following details:—

S.No.	NH. No.	Name of work and estimated cost
1.	24	Four-laining of Ghaziabad-Hapur section including Construction of Hapur bypass (DECF U.P. project) - Rs. 96.50 Crores,
2.	28	Construction of Basti bypass (Phase II) - (U.P.) Rs. 10.00 Crores,
3.	56	Construction of Pili Nadi Bridge at Km. 141 (U.P.) Estimate Cost Rs. 2.47 Crores,
4.&5	1	Proposals reg. improvement in Beas-Amritsar Seciton of NH-1 Rs. 0.80 Crores, (Punjab)

National Highways passing through Punjab and U.P.

1666. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the condition of National Highways passing through Punjab and U.P. is very deplorable;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) All the National Highways passing through the States of Punjab and U.P. are being maintained in traffic worthy condition to the extent possible by undertaking development/ maintenance works from time to time as per their requirements within the available resources.

सड़क निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को सुविधाएं

1667. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क निर्माण हेतु सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा;

(ग) इनमें से प्रमुख सड़कें कौन-कौन सी होंगी और उनकी लंबाई एवं चौड़ाई कितनी-कितनी होंगी तथा इन पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) सड़क निर्माता को कितना सड़क-कर लगाने की अनुमति होगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) निजी क्षेत्र को पहले ही कर रियायत, वित्तीय रियायतें, राजमार्ग परियोजनाओं और उनसे सम्बद्ध सुविधाओं आदि के लिए भूमि जैसी विभिन्न सुविधाएं आफर की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में प्रयास किए गए हैं। 100 करोड़ रु० की कुछेक योजनाओं के साथ इस बारे में शुरूआत की जा चुकी है। 1000 करोड़ रु० मूल्य की परियोजनाएं तैयारी की स्थिति में हैं। अगले पांच वर्षों के दौरान संभावित प्रतिक्रिया के बारे में अभी से बता पाना कठिन है।

(घ) चार-लेन वाली परियोजनाओं पर विभिन्न प्रकार के वाहनों से वसूले जाने वाले शुल्क की अधिकतम दरें सरकार ने अनुमोदित कर दी हैं, जो इस प्रकार हैं:—

कार	—	0.40 रु०/कि०मी०
हलके वाणिज्यिक वाहन	—	0.70 रु०/कि०मी०
ट्रक-बस	—	1.40 रु०/कि०मी०
बहुत-धुरीय वाहन तथा अन्य भारी उपस्कर वाहक	—	3.00 रु०/कि०मी०

Construction of Bridge over Kolab River

1668. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to construct a bridge over the river Kolab in Orissa;

(b) if so, the fund sanctioned for the purpose; and

(c) the steps taken to start the construction work?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) The Central Government is primarily responsible for the development and maintenance of National Highways (NH) only in the country. The responsibility for all other roads lies with the respective State Govts. The bridge, in question, over the river Kolab in Orissa does not form part of the NH Network and hence it is the responsibility of the Govt. of Orissa.

पत्तनों में निजी गोदी

1669. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कांडला पत्तन समेत किन-किन पत्तनों में रक्षित निजी गोदियां हैं;

(ख) क्या कांडला पत्तन में तथा इसके इर्द-गिर्द अन्य लघु एवं मझोले पत्तनों में रक्षित गोदियों का निर्माण कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ग) कांडला पत्तन समेत किन-किन पत्तनों को अब तक रक्षित निजी गोदियों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है; और

(घ) रक्षित निजी गोदियों के मामले में किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन): (क) से (ग) कांडला में बर्थ सं० 6 मै० जी पी कार्पोरेशन लि० बैंकाक को पट्टे पर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मै आई ओ सी, एच पी सी एल और इफ्को को आबद्ध सुविधाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है। अन्य पत्तन केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य नहीं कर रहे है।

(घ) सरकार ने पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

Decline in Share of National Shipping Lines in Overseas Trade

1670. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Shipping Lines continue to lose their share in the country's overseas trade;

(b) if so, what is the comparative percentage of decline in the share of the National Shipping Lines in the country's overseas trade during the last three years;

(c) what are the main causes for the declining trend in the shares of the National Shipping Lines in the country's overseas trade; and

(d) what measures are contemplated by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) There has been a reduction in percentage terms in the carriage of India's overseas trade by Indian vessels during the 8th Plan period. However, in terms of volume, there has been no appreciable reduction. The year-wise share of Indian shipping in India's overseas trade during the 8th Plan period is as under:

Year	Total trade (Indian & Foreign Lines)	Indian Lines	Percentage
	(MILLION TONNES)		(%)
1992-93	122.30	42.66	34.90
1993-94	136.97	46.07	33.60
1994-95	146.55	42.02	28.70
1995-96	166.10	46.00	27.80
1996-97	(Not Available)		